भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3238

16.12.2024 को उत्तर के लिए

जलवायु संकट संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

3238. श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जलवायु संकट से निपटने की दिशा में स्वच्छ ऊर्जा और शीतलन समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक महत्वपूर्ण कदम है, यदि हां, तो क्या क्वाड राष्ट्रों (आस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका) ने विलमिंगटन घोषणा जारी की है जो सतत ऊर्जा समाधानों के प्रति क्वाड देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और लचीली और सुरक्षित वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण के लिए एक रूपरेखा का विस्तृत ब्यौरा देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों से ली गई/ली जाने वाली सहायता सहित स्वीकृत/खर्च की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): क्वाड देशों का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली, विविधतापूर्ण स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने की दिशा में उन नीतियों, प्रोत्साहनों, मानकों और निवेशों को संरेखित करने हेतु सहयोग को सुदृढ़ करना है, जिनसे सामूहिक ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हो, पूरे क्षेत्र में नए आर्थिक अवसर पैदा हो सकें और दुनिया भर में, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थानीय श्रमिकों और समुदायों को लाभ मिले।

क्वाड साझेदारी, नीति निर्णय और सार्वजनिक वित्त के माध्यम से सहयोगी और साझेदार स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में निजी क्षेत्र के पूरक और उच्च-मानक वाले निवेश को उत्प्रेरित करने की प्रतिबद्धता को क्रियान्वित करने के लिए काम करती है। सुरक्षित और विविधतापूर्ण स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएँ

हिंद-प्रशान्त क्षेत्र की सामूहिक ऊर्जा सुरक्षा, अपने-अपने जलवायु लक्ष्यों और भविष्य में वैश्विक स्तर पर निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना का एक अभिन्न अंग हैं। वर्ष 2023 में, क्वाड लीडरों ने 'क्वाड क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन डायवर्सिफिकेशन प्रोग्राम' की घोषणा की, जिसका उद्देश्य हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और विविधतापूर्ण स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में सहयोग प्रदान करना है।

यद्यपि, क्वाड द्वारा जलवायु अनुकूल और सुरक्षित वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने के लिए कोई निर्धारित रूपरेखा नहीं है, फिर भी, क्वाड विलमिंगटन घोषणा के एक हिस्से के रूप में, भारत और अमेरिका के लीडरों ने दिनांक 21 सितंबर, 2024 को अमेरिका के डेलावेयर के विलमिंगटन में अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान "सुरक्षित और सुनिश्चित वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए अमेरिका-भारत रोडमैप" का स्वागत किया, ताकि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और घटकों के अमेरिका और भारत में होने वाले विनिर्माण के माध्यम से सुरक्षित और सुनिश्चित स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के विस्तार में तेजी लाई जा सके। इस रूपरेखा के तहत, अमेरिका और भारत ने अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, पावर ग्रिड और पारेषण प्रौद्योगिकियों, अधिक कुशल शीतलन प्रणाली, उत्सर्जन रहित वाहनों और अन्य नई स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए संपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में संचालित परियोजनाओं में सहयोग प्रदान करने के लिए 1 बिलियन अमरीकी डालर का बहुपक्षीय वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है।

दिनांक 21 सितंबर 2024 को विलमिंगटन में छठे क्वाड लीडर्स समिट में जारी क्वाड फैक्ट शीट में बैटरी आपूर्ति श्रृंखला में क्वाड भागीदारों द्वारा साझा की जाने वाली पूरक क्षमताओं को नोट किया गया है, और हमारे अपने-अपने उद्योगों में खनिज उत्पादन, पुनर्चक्रण और बैटरी निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए निकट-अवधि के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लिया गया है। इस घोषणापत्र में ऊर्जा के किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की भी घोषणा की गई, जिसमें किफायती, उच्च कुशलता वाली शीतलन प्रणालियों का उपयोग और विनिर्माण शामिल है, ताकि जलवायु-संवेदनशील समुदायों को बढ़ते तापमान के अनुकूल होने में सक्षम बनाया जा सके और साथ ही बिजली ग्रिड पर दबाव कम किया जा सके। भारत ने फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशेल्स में नई सौर परियोजनाओं

में 2 मिलियन अमरीकी डालर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। दिनांक 26 नवंबर, 2024 को, हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के इन देशों में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु विदेश मंत्रालय (एमईए) तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के बीच परियोजना कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में आईएसए, भारत के वित्तीय सहयोग से कोमोरोस, फिजी, मेडागास्कर और सेशेल्स को कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करेगा।

*****